भोजन में असफल होना

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (सामाजिक न्याय) से संबंधित है।

द हिन्दू

01 अक्टूबर, 2021

बाल कुपोषण पर आधारित हाल ही के आंकड़े स्कूली भोजन की गुणवत्ता के महत्व को रेखांकित करते हैं।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रधानमंत्री पोषण योजना की 2025-26 तक मंजूरी एक महत्वपूर्ण समय में आयी है जब वास्तविक आय में गिरावट आ रखी है और कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव ने परिवारों की अच्छा पोषण सुनिश्चित करने की क्षमता को प्रभावित किया है।

दिसंबर 2020 में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एनएफएचएस -5 के पहले चरण के निष्कर्ष चौंकाने वाले थे: 13 राज्यों में बचपन में स्टंटिंग (उम्र के हिसाब से कद कम होना) बढ़ी, बच्चों और महिलाओं में एनीमिया का उच्च प्रसार था, और 12 राज्यों में वेस्टिंग (कद और उम्र के हिसाब से वजन कम होना) एक गंभीर चिंता थी।

ये आंकड़े पिछले सर्वेक्षण अवधि के दौरान कुपोषण के बिगड़ते संकट को उजागर करते है, जिससे लाखों बच्चों को पूरी तरह से उत्पादक वयस्क जीवन से वंचित करने का खतरा है। मजबूत बजटीय प्रतिबद्धता से समर्थित इस छिपे हुए संकट को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास करने होंगे। 11.8 करोड़ बच्चों को कवर करने वाले सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में केंद्र समर्थित गर्म भोजन कार्यक्रम को उच्च रक्ताल्पता वाले चिन्हित आकांक्षी जिलों और क्षेत्रों में पोषक तत्वों के साथ पूरा किया जाएगा।

इस योजना को पूर्व-प्राथमिक बच्चों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है।यह योजना सामाजिक लेखा परीक्षा, ताजा उपज के स्रोत के लिए स्कूल पोषण उद्यान का निर्माण, प्रदाता के रूप में किसान-उत्पादक संगठनों की भागीदारी, और स्थानीय खाद्य परंपराओं पर जोर देती है। हालांकि ये सकारात्मक विशेषताएं हैं, कुपोषण उन्मूलन की गति वार्षिक बजटीय परिव्यय पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करती है और पोषण के कार्य का प्रमाण मापने योग्य परिणामों में निहित होगा।

प्रधानमंत्री पोषण योजना के लिए वित्तीय समर्थन को लोचदार होना चाहिए, हालांकि अभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से ₹31,733 करोड़ सहित कुल ₹1,30,794 करोड़ को पांच साल की अवधि में अनुमोदित किया गया है।

अगर बाल विकास के मापदंडों (Parameters) की बात करें जैसे स्टंटिंग एवं वेस्टिंग, एनीमिया आदि को मापने के लिए एक लंबे समयकाल की आवश्यकता होती है। एनीमिया और कम वजन जैसी समस्याओं में भी समय लगता हैं। सरकार को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि सक्षम आंगनवाड़ी-मिशन पोषण 2.0, जो पोषण अभियान और आंगनवाड़ियों, शिशु गृहों और किशोरियों को कवर करने वाली योजनाओं को समाहित करता है, अपने पूर्ववर्ती घटकों के भागों की तुलना में वित्तीय रूप से अधिक मजबूत है।

अगर सरकार किसी योजना को दूसरी योजना में समाहित करती है तो सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि इन समावेशित व्यक्तिगत योजनाओं के लिए जो पिछला संयुक्त परिव्यय था उसकी तुलना में वर्तमान बजट अनुमान में सार्थक वृद्धि होनी चाहिए।

पोषाहार नियोजन के संबंध में, नवीकृत योजना में सूक्ष्म पोषक तत्वों और प्रोटीन की कमी को पूरा करने वाले आहारों की अधिक विविधता को शामिल किया जाना चाहिए।

ऐसे समय में जब खाद्य मुद्रास्फीति में बढोत्तरी होने के बाद भी कोई कदम नही उठाया जा रहा और ऐसा समय जब महामारी से प्रेरित आय में गिरावट ने आवश्यक खपत को कम कर दिया है तब स्कूल, सामुदायिक केन्द्रों और चाइल्डकेयर केंद्रों में पोषण को सुनिश्चित करना और उसका आधार का विस्तार करना महत्वपूर्ण है।

पिछले वर्ष की तुलना में महामारी के दौरान मिड-डे-मील योजना के लिए खाद्यान्न की कम उठान और कई राज्यों में खराब खाद्य वितरण तंत्र से खतरे की घंटी बजनी चाहिए, क्योंकि भारतीयों की एक पीढ़ी का भविष्य दांव पर है।

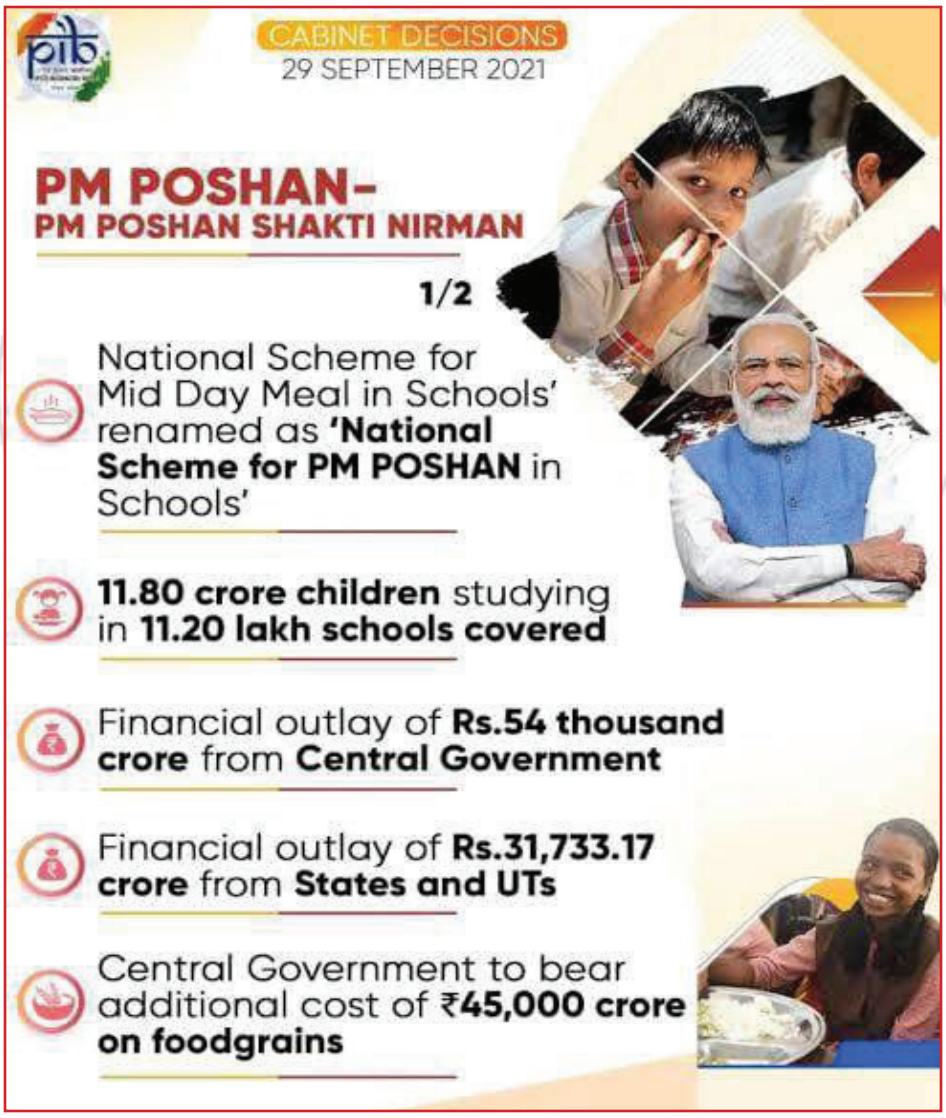

जीएस वर्ल्ड टीम इनपुट

IN THE NEWS

पीएम पोषण योजना के बारे में :-

- पीएम पोषण ***"मिड-डे-मील योजना"*** का एक नया संस्करण है, जिसका अर्थ है "पीएम पोषण शक्ति निर्माण"। नए नामकरण के साथ, केंद्र ने 'बाल पोषण' की दिशा में एक बड़ा प्रयास शुरू किया है।
- यह योजना वर्ष 2022 से सरकारी स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले लगभग 24 लाख छात्रों को कवर करेगी।
- इसके तहत सरकार, स्कूलों में 'पोषाहार उद्यानों' को बढ़ावा देगी। छात्रों को अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने हेतु उद्यान स्थापित किये जायेंगे।
- पीएम पोषण योजना 5 और वर्षों तक चलेगी। यह 2021-2022 से 2025-26 तक चलेगी।
- केंद्र सरकार ने 54,062 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ इस योजना को मंजूरी दी है।
- राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन ने 31,733 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी है।
- इस चरण में, योजना 11.20 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 11.80 करोड़ बच्चों को कवर करेगी।
- इन बच्चों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार 45,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत वहन करेगी।
- इस योजना का कुल बजट 1,30,795 करोड़ रुपये है।
- यह केंद्र प्रायोजित योजना सरकारी स्कूलों के साथ-साथ सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूली बच्चों को कवर करेगी।

Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. पीएम पोषण योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. यह योजना मिड-डे-मील के राष्ट्रीय कार्यक्रम का स्थान लेगी।
2. यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं-

(a) केवल 1 **(b)** केवल 2

(c) 1 एवं 2 दोनो **(d)** न तो 1 न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements about PM Nutrition Scheme-

1. This scheme will replace the national program of Mid-Day-Meal.
2. It is a central sector scheme.

Which of the above statement is/are true-

(a) Only 1 **(b)** Only 2

(c) Both 1 and 2 **(d)** Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. भारत मे बच्चों के स्तर पर पोषण की वर्तमान स्थिति की चर्चा करें। केन्द्र सरकार द्वारा मिड-डे-मील योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री पोषण योजना इस समस्या को किस प्रकार हल करने में सहायक सिद्ध होगी? (250 शब्द)

Q. Discuss the present status of nutrition at the level of children in India. In the place of Mid-Day-Meal Scheme How the Pradhan Mantri Poshan Yojana brought by the Central Government will prove to be helpful in solving this problem? (250 Words)

GS World
Committed To Excellence

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।